प्रभात खबर 7.9.2015

बोकारो न्यायालय. जस्टिस डीएन पटेल ने कहा : इ-कोर्ट में

10 अक्तूबर से पहले करें 15 मामलों का निष्पादन

संवाददाता, बोकारो

बोकारो न्यायालय में रविवार को हाई कोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि 10 अक्तूबर से पहले इ-कोर्ट के माध्यम से कम से कम 15 केस का निष्पादन होना चाहिए. कम समय में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए एसपी को भी कहा गया है. श्री पटेल ने कहा : इ-कोर्ट को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी जरूरतें पूरी की जायेंगी. ई-कोर्ट के निरीक्षण के उपरांत श्री पटेल ने कोर्ट कैंपस का जायजा लिया. प्रधान जिला न्यायाधीश संजय प्रसाद को व्यवहार न्यायालय के दोनों भवन के ऊपर 300 लोगों को एक साथ बैठने की क्षमता वाले दो वातानुकूलित न्याय सदन बनाने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि जमीन को लेकर न्याय सदन निर्माण का काम लंबित पड़ा था.

न्यायालय के दोनों भवनों में लगेंगे चार लिफ्ट : श्री पटेल ने कहा : दोनों कोर्ट भवन में 10 से 15 लोगों की क्षमता वाले दो-दो लिफ्ट भी लगाये जायेंगे. इ-कोर्ट के लिए अलग से हाई पावर जेनेरेटर लगाने का आदेश भी दिया. कोर्ट का बरामदा भी दो फुट चौड़ा किया जायेगा. इस दौरान भवन निर्माण विभाग के अभियंता आरके राणा भी मौजूद थे. श्री पटेल ने प्रधान जिला न्यायाधीश से कहा कि उक्त सभी कामों के लिए प्रोजेक्ट बना कर तुरंत हाई कोर्ट को भेजे. श्री पटेल ने बोकारो के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें न्यायिक पदाधिकारियों को डीएलएसए के मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराने और सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अधिक से अधिक संख्या में मध्यस्थता केंद्र में केस ट्रांसफर करने का निर्देश दिया.

कोर्ट निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों को निर्देश देते हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल.

दैनिक भास्कर 7.9.2015

विचाराधीन कैदियों की सुनवाई ई कोर्ट से करें

बोकारो व्यवहार न्यायालय परिसर में ई कोर्ट का शुभारंभ

केंद्र में अधिक मामलों को सुलझाएं : मुख्य न्यायाधीश

भास्कर न्यूज | बोकारो

विचाराधीन कैदियों की सुनवाई ई कोर्ट के माध्यम से किया जाए ताकि कैदियों को जेल से कोर्ट तक लाने और ले जाने की झंझट से छुटकारा मिल सके। यह कहना है झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल का। उन्होंने बोकारो व्यवहार न्यायालय परिसर में ई कोर्ट का शुभारंभ करने के बाद न्यायिक पदाधिकारियों और जेल अधीक्षक विजय राजेश बारला को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को लाने और ले जाने में परेशानी होती है, ऐसे में उनकी सुनवाई ई कोर्ट में ही कर दी जाए। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता केंद्र बेहतर न्याय दिलाने का उचित माध्यम है। अगर किसी मामले में थोड़ी भी सुलह की गुंजाइश हो तो तुरंत उसे मध्यस्थता केंद्र में भेज मामले का निष्पादन कराया जाए। इस मौके पर न्यायिक पदाधिकारी सह सचिव नवनीत कुमार ने कहा कि मध्यस्थता केंद्र में अधिक से अधिक मामले भेजे जाएं, ताकि कोर्ट का बोझ कम हो सके। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने मुख्य न्यायाधीश का बोकारो के न्यायिक पदाधिकारियों की ओर से स्वागत तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सीता राम रवानी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

8.9.15

SECRETARY
DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY
BOKARO

हिन्दुस्तान दि. 7.9.2015

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल ने ई-कोर्ट का किया निरीक्षण

ई-कोर्ट में बंदी की करें पेशी

बोकारो | प्रतिनिधि

सुझाव दिए

- बोकारो व्यवहार न्यायालय में होगा डीएलएस का अपना न्याय सदन भवन
- न्यायिक पदाधिकारियों को मिडिएशन सेंटर में मामलों को भेजने का सुझाव

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल ने रविवार को बोकारो व्यवहार न्यायालय में ई-कोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों से कहा कि ई-कोर्ट को नियमित करें। ताकि जेल में बंद विचाराधीन कैदी को कोर्ट लाए बगैर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हो सके। इससे समय और रूट के खतरे से निजात मिलेगी। ई-कोर्ट में कांडों के नियमित ट्रॉयल से मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो पाएगा।

उन्होंने निरीक्षण के दौरान व्यवहार न्यायालय में बने ई-कोर्ट से चास जेल के प्रभारी जेल अधीक्षक से बात की और जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इससे पहले न्यायाधीश के आगमन पर बोकारो के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद, सब जज मनीष रंजन समेत तमाम न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ता ने उनका स्वागत किया।

मेडिएशन सेंटर से मामलों का निपटारा : ई-कोर्ट के निरीक्षण के बाद जस्टीस डीएन पटेल बोकारो के न्यायिक पदाधिकारियों और डीएलएसए के मध्यस्त सदस्यों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक मामलों को मेडिएशन सेंटर में भेजने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालयों पर केस का दबाव बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने में कुछ समय लग जाता है।

इसके निराकरण के लिए विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से चलने वाला लोक अदालत केस की संख्या को कम करने का समुचित माध्यम है। मेडिएशन सेंटर में दोनों पक्षों की सहमति पर फैसले लिए जाते हैं। इसमें किसी की हार नहीं होती। इसलिए न्यायिक पदाधिकारी अधिक-से अधिक मामलों को मेडिएशन सेंटर में भेज कर उसे निपटाने का काम करें।

न्याय सदन का होगा अपना भवन : जस्टीस डीएन पटेल के बोकारो आगमन पर प्रस्तावित न्याय सदन की चर्चा न्यायिक पदाधिकारियों ने की। इससे जस्टीस ने सहमति जताई। व्यवहार न्यायालय की बिल्डिंग में ऊपर के तल्ले में न्याय सदन बनाया जाएगा। इसमें डीएलएसए मेडिएशन सेंटर में आने वाले मामलों का निपटारा करेगी।

रविवार को बोकारो पहुंचे झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल । • हिन्दुस्तान

मध्यस्तों की भूमिका अहम : न्याय सदन में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ-साथ मध्यस्तों की भूमिका अहम होगी। बोकारो में लगभग 15 मध्यस्त है, जो लोक अदालतों में आने वाले मामलों को निपटाने में अहम भूमिका में होते हैं। वे दोनों पक्षों के बीच सुलह का तथ्यपूर्ण रास्ता तैयार करते हैं।

प्रभात खबर 7.9.2015

इ-कोर्ट में नियमित रूप से सुनवाई करें : डीएन पटेल

- हाइकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने बोकारो कोर्ट का निरीक्षण किया
- कोर्ट भवन के ऊपर बनेगा 350 लोगों की क्षमता वाला दो न्याय सदन

बोकारो. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के एग्जिक्यूटिव चेयरमैन डीएन पटेल रविवार को बोकारो न्यायालय पहुंचे. श्री पटेल के साथ झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार भी थे. न्यायाधीश के स्वागत के लिए न्यायालय परिसर में प्रधान जिला न्यायाधीश संजय प्रसाद और सभी न्यायिक पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे. इस दौरान श्री पटेल ने बोकारो न्यायालय में हाल ही में बने अत्याधुनिक इ-कोर्ट का निरीक्षण किया. यहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चास मंडल कारा के प्रभारी जेल अधीक्षक विजय राजेश बारला से वीसी सिस्टम के बारे में बातचीत की. न्यायिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री पटेल ने कहा कि इ-कोर्ट का संचालन अब नियमित रूप से होना चाहिए.

वीसी के जरिये जेल अधीक्षक को निर्देश देते श्री पटेल. (पढ़ें पेज पांच भी)

9/9/15

SECRETARY
DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY

प्रभात खबर जागरण दि. 9.9.2015

सिविल कोर्ट में बनेगा न्याय सदन

कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी, डीएसपी, अधिवक्ता व ई-कोर्ट की व्यवस्था देखते हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल।

- न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने किया न्यायालय का निरीक्षक, ई-कोर्ट भी देखा

जागरण संवाददाता, बोकारो : सिविल कोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे झालसा के एक्सक्यूटिव चेयरमैन सह झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायामूर्ति डीएन पटेल ने कोर्ट परिसर में न्याय सदन बनाने का आदेश दिया। इनके साथ सदस्य सचिव झालसा नवनीत कुमार भी थे। निरीक्षण के दौरान न्यायमूर्ति ने ई कोर्ट भी देखा। यहां रेगुलर ट्रायल शुरू करने का आदेश भी उन्होंने दिया।

इस दौरान एनआइसी के अधिकारियों को भी उन्होंने कई निर्देश दिया। कोर्ट परिसर में प्रधान जिला जज समेत सभी न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों ने न्यायमूर्ति व सदस्य सचिव का स्वागत किया। झालसा के अधिवक्ताओं से भी वे मिले। जनरेटर की पर्याप्त प्रयाप्त व्यवस्था करने का भी उन्होंने निर्देश दिया।

चास को अपराधमुक्त बनाने की गुहार

संस, चास : जागृति संघ ने चास थाना प्रभारी कमल किशोर से भेंट कर चास को अपराध मुक्त बनाने की मांग की है। अध्यक्ष मनोज राय ने कहा कि चास में अपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। आये दिन चोरी, छिनतई आदि से लोग परेशान हैं। ऐसे में चास के नए थानेदार से लोगों को काफी उम्मीद है। मौके पर रमेश सिंह, अशोक प्रमाणिक, दिलीप स्वर्णकार, जितेन्द्र, अमर स्वर्णकार, बबलू प्रमाणिक, जयदेव दत्ता, साधन दे, कनवर साव, अनूप घोषाल, तपन चक्रवर्ती, अतुल दत्ता, सनातन पाल, अर्जुन आचार्या, अनुपम दास उपस्थित थे।

9/9.9.15

SECRETARY
DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY
BOKARO